आईएलआर (1996) 2 पी एंड एच 124 : (1996) 4 एसएलआर 828 (डीबी) : 1996 लैब आईसी 2605

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

(न्यायमूर्ति अशोक भान और न्यायमूर्ति पीके जैन के समक्ष)

भगत सिंह और अन्य... याचिकाकर्ताओं;

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ... उत्तरदाताओं।

1995 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 2323

20 दिसंबर, 1995 को हुआ फैसला

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226/227 - पंजाब लोक निर्माण (सिंचाई शाखा) पटवारी राज्य सेवा, तृतीय श्रेणी, नियम, 1955 (हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया गया) - आरएलएस 10 से 12 - चयन समिति द्वारा बनाए गए नहर पटवारियों के चयन को चुनौती - नहर पटवारियों के चयन के लिए बनाए गए नियम - हालांकि चयन समिति ने चयन के लिए अपने स्वयं के मानदंड तैयार किए - चयन समिति के गठन या किसी भी साक्षात्कार आयोजित करने के लिए किसी भी नियम में कोई प्रावधान नहीं है - चयन समिति के गठन या किसी भी साक्षात्कार के लिए किसी भी नियम में कोई प्रावधान नहीं है । चयन समिति द्वारा की गई नियुक्तियां अधिकारहीन और अवैध हैं।

और रूप:

कि नहरी पटवारियों की भर्ती के लिए और उनकी सेवा शर्तों के लिए सांविधिक नियम, 1955 अधिनियमित किए गए हैं। ये नियम अपने आप में नहरी पटवारियों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पूरी योजना प्रदान करते हैं। भर्ती की विधि और नियुक्ति का तरीका नियम 10 से 12 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। नियम 8 के अनुसार, सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियां संभागीय अधिकारियों द्वारा की जाएंगी।

(पैरा 33)

आगे कहा गया:

इस प्रकार, किसी भी नियम में किसी अन्य चयन समिति के गठन या पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(पैरा 33)

आगे कहा गया:

यह कि चयन समिति का गठन या प्रतिवादी-राज्य द्वारा उसके संविधान को दिया गया अनुमोदन, अनुबंध आर 1 के तहत नियम, 1955 का सीधा उल्लंघन है। उक्त चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर साक्षात्कार की आवश्यकता उपयुक्तता के रूप में चयन के लिए एक अतिरिक्त आवश्यकता है जिसे वैधानिक नियमों द्वारा अनुमति नहीं दी गई है और इसे अवैध और बिना अधिकार के कहा जाएगा।

(पैरा 34)

आगे कहा गया:

चूंकि चयन समिति का गठन एक प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए कार्यकारी निर्देशों द्वारा किया गया था, इसलिए इसके पास नहर पटवारियों के लिए चयन करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं था । उक्त चयन समिति के पास चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने का भी कोई अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र नहीं था। फिर भी, चयन समिति को चयन के लिए कोई मानक या आधार निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह चयन के नियम को कानून बनाने के बराबर होगा।

(पैरा 37)

भारत का संविधान- अनुच्छेद 226/227 - पंजाब लोक निर्माण (सिंचाई शाखा) पटवारी राज्य सेवा, तृतीय श्रेणी, नियम, 1955 - निरंकुशता का सिद्धांत - अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की स्थापना - 'नियम' अब बोर्ड के माध्यम से किए गए चयन का पालन नहीं करते हैं - क्या नियम, 1955 को निरंकुशता के सिद्धांत के आधार पर निरस्त किया गया था - क्या नियम 1955 को अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया गया था - कानून के सिद्धांत को लागू करने के लिए आयोजित किया गया था और इसके बजाय एक विपरीत अभ्यास होना चाहिए।उपयोग में होना - केवल यह तथ्य कि एक बार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नहर पटवारी के पद पर भर्ती की गई थी, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि नियमों को निरंकुशता के सिद्धांत के आधार पर निरस्त कर दिया जाता है।

और रूप:

यह कि निरंकुशता के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए, विचाराधीन क़ानून को लंबे समय तक अप्रयुक्त होना चाहिए और इसके बजाय एक विपरीत अभ्यास उपयोग में होना चाहिए। इस सिद्धांत के संचालन के लिए इस तरह के चरित्र के विपरीत उपयोग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि की आवश्यकता होती है जो समुदाय की ऐसी पूरी तरह से स्थापित आदत

का अनुमान लगाने के लिए व्यावहारिक है ताकि कानून का मुकाबला किया जा सके या निरसन को रद्द किया *जा सके*।

(पैरा 24)

आगे कहा गया:

कि पिछले 30 वर्षों के दौरान एक बार नहरी पटवारियों के पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवाओं के माध्यम से की गई थी। चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर यह कहना पर्याप्त नहीं है कि नियम, 1955 को निषेध के सिद्धांत के आधार पर निरस्त कर दिया गया है।

(पैरा 27)

आगे कहा गया:

यदि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने नियम, 1955 का उल्लंघन करते हुए भी वर्ष 1974 में केवल एक बार नहर पटवारियों के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की थी, तो उक्त नियमों की वैधता और बाध्यकारी प्रभाव को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 27)

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226/227 - पंजाब लोक निर्माण (सिंचाई शाखा) पटवारी राज्य सेवा, तृतीय श्रेणी, नियम, 1955 - छूट - याचिकाकर्ता स्वेच्छा से चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए - क्या उन्हें अब यह दलील देने की अनुमति दी जा सकती है कि चयन समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया था - यह माना जाता है कि छूट देने वाले व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाता है और पूरी जानकारी के साथ वह जानबूझकर इसे छोड़ देता है - यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने छूट दी है। चुनौती देने का उनका अधिकार।

आयोजित:

यह कि कोई छूट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने माफी की है, उसे उसके अधिकार के बारे में पूरी तरह से सूचित नहीं किया जाता है और इस तरह के अधिकार की पूरी जानकारी के साथ, वह जानबूझकर इसे माफ कर देता है ।

(पैरा 42)

आगे कहा गया:

उत्तरदाताओं द्वारा यह नहीं बताया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को पहले से कोई संचार भेजा गया था जिसमें यह संकेत दिया गया था कि पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें किसी भी चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा, न ही उन्हें उनके पदनामों के साथ उन व्यक्तियों के बारे में सूचित किया गया था जिन्होंने साक्षात्कार के लिए चयन समिति का गठन किया था। याचिकाकर्ताओं को चयन समिति द्वारा निर्धारित तथाकथित मानदंडों के बारे में भी कभी नहीं बताया गया , जिसके आधार पर नहर पटवारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाना था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले याचिकाकर्ताओं ने समिति के गठन या चयन के लिए निर्धारित मानदंडों को चुनौती देने के अपने अधिकार को छोड़ दिया।

(पैरा 44)

आगे कहा गया:

यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने चयन समिति के गठन और चयन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदंडों को चुनौती देने के अपने अधिकार को रद्द कर दिया है, जो नियम, 1955 के *विपरीत* है।

(पैरा 44)

आगे कहा गया:

यह कि चयन समिति का गठन अपने आप में अवैध और वैधानिक नियमों के विपरीत था। इस चयन समिति के पास उक्त चयन के लिए कोई मानदंड निर्धारित करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं था। समिति द्वारा किया गया चयन न केवल नियमों के विपरीत है बल्कि चयन के मानदंडों का उल्लंघन है।

(पैरा 40)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आरके मलिक।

हरियाणा के एडवोकेट जनरल एच.एल.सिब्बल, हरियाणा के एडवोकेट जनरल कमल शर्मा के अलावा उत्तरदाताओं की ओर से एन अंबर । 1 से 7.

धर्मवीर शर्मा, प्रतिवादियों के वकील एनअम्बर 8 से 16, 18 से 30, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 45 और 47।

सूर्य कांत, वकील, प्रतिवादियोंके लिए 14 से 22, 24 से 26 31 और 32।

न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा सुनाया गया था

न्यायमूर्ति पी.के.-- इस निर्णय से 596, 2323, 2589, 2923, 2938, 3153 3163, 3341, 3384, 3587, 3655, 3772, 3814, 4268, 4269, 4270, 4283, 4362, 4369, 4370, 5499, 5516, 6316, 6326, 6390, 6553, 6816, 6882, 7958, 8451, 9074, 9739, 9743, 10007, 10170, 10171, 10201, 10248, 10531, 10811, 11040, 11109, 11560, 11858, 12169, 12170, 12188, 12938, 13142, 13307, 13563, 13986, 14149, 14838, 14908, 14918, 14927, 15013, 15057, 15105, 15283 और 15458 1995 की इन सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा राज्य के सिंचाई विभाग में नहर पटवारियों के विवादित चयन को रद्द करने और इसके परिणामस्वरूप निजी प्रतिवादियों की नियुक्ति के लिए भी कमोबेश एक ही प्रार्थना की है। परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए भी अनुरोध किया गया है कि आधिकारिक प्रतिवादियों को उक्त विभाग में नहर पटवारियों के उक्त पदों पर कानून के अनुसार सख्ती से नियुक्ति करने का निर्देश दिया जाए।

2. प्रतिद्वंद्वी मामलों की सराहना के उद्देश्य से, हम 1995 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2323 (*भगत सिंह* बनाम *हरियाणा राज्य*) में निर्धारित तथ्यों का उल्लेख करने का प्रस्ताव करते हैं।

1995 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2323 में, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि राज्य के सिंचाई विभाग में नहर पटवारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को पंजाब लोक निर्माण (सिंचाई शाखा) पटवारी राज्य सेवा, श्रेणी III, नियम, 1955 (इसके बाद 'नियम, 1955' के रूप में संदर्भित) के रूप में जाना जाने वाला वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। 1966. उक्त नियमों के अनुसार पटवार प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन संभागीय अधिकारी द्वारा किया जाना है। स्वीकृत उम्मीदवारों को जिलेदारों के साथ पटवार प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्त किया जाना है। पटवार प्रशिक्षण पूरा होने के बाद स्वीकृत उम्मीदवारों को पटवार परीक्षा में शामिल होना होता है , सफल उम्मीदवारों को सर्कल रजिस्टर पर लाया जाता है। जब कभी पद उपलब्ध होते हैं, नियुक्तियां पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों में से की जाती हैं और पटवार परीक्षा में प्राप्त योग्यता/स्थिति के क्रम में सर्कल रजिस्टर पर वहन की जाती हैं । उनकी *पारस्परिक* वरिष्ठता का निर्धारण पटवार परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में किया जाना है ।

4. याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि उनका चयन संभागीय अधिकारी द्वारा किया गया था और पटवार प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पटवार प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, वे 25 अप्रैल, 1992 से 28 अप्रैल, 1992 तक आयोजित पटवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे । सभी याचिकाकर्ताओं ने पटवार परीक्षा पास की है । पटवार परीक्षा में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए पद/अंक निम्नानुसार हैं:-

"नहीं। और याचिकाकर्ता का नाम	पटवार परीक्षा के कुल अंक	पटवार परीक्षा में प्राप्त अंक
1. भगत सिंह	375	302

2. कृष्ण कुमार	375	289
3. बलदेव सिंह	375	289
4. बलराज सिंह	375	288
5. धरमिंदर कुमार	375	285½
6. राज कुमार	375	279
7. ओम प्रकाश	375	303
8. राधेश्याम	375	280
9. सुरिंदर कुमार	375	282½
10. सिरी निवास	375	280½
11. पवन कुमार	375	308½
12. राम मेहर	375	279
13. राजेश कुमार	375	284
14. मोमन राम	375	287
15. गुरशरण सिंह	375	289
16. नरिंदर कुमार	375	277"

उक्त नियमावली 1955 के नियम 12 के अनुसार पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर याचिकाकर्ताओं के नाम कैथल स्थित भाखड़ा जल सेवा वृत्त के सर्किल रजिस्टर में दर्ज किए गए थे तथा नहरी पटवारियों के पदों पर नियुक्तियां योग्यता के क्रम में की जानी थी। तथापि, नियम, 1955 के विपरीत, पांच सदस्यों वाली एक चयन समिति का गठन किया गया था जिसने पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यथयों का साक्षात्कार लिया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चयन समिति ने निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर लागू चयन को अंतिम रूप दिया: -

(i) पटवार परीक्षा के लिए आवंटित अंक:	375
(ii) साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक:	25
	कुल अंक: 400

चयनित उम्मीदवारों की सूची नियुक्ति के लिए भाखड़ा जल सेवा सर्कल, कैथल को भेजी गई थी। ऐसे उम्मीदवारों के विवरण और पटवार परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार हैं:-

"प्रतिवादी संख्या।	उत्तरदाता का नाम	पटवार परीक्षा में प्राप्त अंक
8.	जगमाल सिंह	272
9.	राजीव कुमार	284
10.	ओम प्रकाश के पुत्र राम फल	272
11.	राम फल	265
12.	राम निवास	259

13.	अशोक कुमार	288
14.	सुरेश कुमार	280
15.	मोहन लाल	269½

16.	सुरिंदर राठी	235
17.	सुनील कुमार	257
19.	ओम प्रकाश	262
21.	जसबीर सिंह	262
26.	हरीश चंदर	261½
29.	धरम पाल	257
30.	भाग मल	282
31.	संतोख सिंह	274
33.	हरि ओम सिंह	273
34.	राजेश कुमार	286
35.	संजीव कुमार	262
36.	रोहताश	277

41.	जय प्रकाश	267½
42.	रमेश चंद	246
45.	दिल बाग सिंह	238
46.	अशोक कुमार	264½
47.	फल सिंह	273½"

याचिकाकर्ताओं ने निजी उम्मीदवारों के चयन और नहर पटवारी के रूप में उनकी नियुक्तियों को अवैध, असंवैधानिक, मनमाना और नियम 1955 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है । यह आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा चयन समिति का गठन कानूनन खराब है क्योंकि यह नियम, 1955 के विपरीत है जो स्व-निहित हैं और किसी भी कार्यकारी निर्देशों द्वारा परिवर्तित या संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। आगे यह आरोप लगाया गया है कि चयन समिति के पास नहर पटवारियों के चयन के लिए स्वयं का कोई मानदंड निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं थी, न ही वैधानिक नियमों में कोई प्रावधान है और न ही साक्षात्कार के लिए कोई अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नहर पटवारियों के रूप में निजी उत्तरदाताओं के चयन और नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को वैधानिक नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

6. प्रतिवादियों को प्रस्ताव की सूचना दी गई।

7. अधिकारी-प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से दायर एक अलग लिखित बयान में, यह कहा गया है कि नहर पटवारियों की सेवाएं वैधानिक नियम, 1955 द्वारा शासित होती हैं, लेकिन इन नियमों को पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश के संयोजन में लागू किया जाना है। (पंजाब), चंडीगढ़, दिनांक 27 मार्च, 1962 के पत्र सं. 3124-48/05/1741/58, जिसके तहत अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से सिंचाई बुकिंग क्लर्क या अपरेंटिस सिंचाई बुकिंग क्लर्क के पद पर भर्ती की जानी है। इन सेवा नियमों और अनुदेशों को सरकारी आदेशों के साथ पढ़ा और लागू किया जाना है कि सभी नियुक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से उम्मीदवारों की मांग करके की जानी आवश्यक हैं। चूंकि रोजगार कार्यालय/अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती को अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए मंडल स्तर पर सर्किल रजिस्टर रखने और इसके आधार पर की जा रही नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है।

8. यह भी बताया गया है कि वर्ष 1992 में विभिन्न फील्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स द्वारा बड़ी संख्या में नहरी पटवारियों की रिक्तियों की सूचना दी गई थी। उक्त रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने मुख्य अभियंता/मंडल नहर अधिकारियों के नियंत्रण ाधीन केन्द्रीय रूप से नहर पटवार परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया है। उक्त परीक्षा चार केंद्रों पर आयोजित की गई थी जहां विभिन्न मंडलों से बने राज्य के चार क्षेत्रों के उम्मीदवार अप्रैल, 1992 में आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुए थे। सफल उम्मीदवारों ने राज्य के विभिन्न जिलों के रोजगार कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत कराया। प्रतिवादी-राज्य ने नहर पटवारियों के 427 पदों को अधीनस्थ चयन बोर्ड के दायरे से बाहर कर दिया था- 4 अक्टूबर, 1994, 25 जनवरी, 1995 की अधिसूचनाओं के माध्यम से और सरकार द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति के लिए 2 मार्च, 1995 के सरकारी पत्र संख्या 40/30/94-3 आईडब्ल्यू के माध्यम से। ज्ञापन संख्या 40/30/94-3 आईडब्ल्यू दिनांक 6 अक्टूबर, 1994 (अनुलग्नक आर 1)। पात्र उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित किया गया था और उक्त चयन समिति द्वारा साक्षात्कार दिया गया था। समिति ने शैक्षणिक योग्यता, नहर पटवारी

परीक्षा में योग्यता , अनुभव और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों जैसे खेल आदि पर विचार करने के बाद निर्धारित मानदंडों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया और नियुक्ति के लिए सरकार को नामों की सिफारिश की। यह भी कहा गया है कि चयन समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के बाद योग्यता के आधार पर किया गया है, न कि केवल नहर पटवार परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर , जो अनिवार्य रूप से और मूल रूप से एक योग्यता प्रशिक्षण परीक्षा है।

9. यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि मंडल स्तर पर सर्कल रजिस्टर को बनाए रखने की प्रथा निरस्त हो गई थी, इसलिए हरियाणा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1974 में राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित करने और सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करने के बाद नहर पटवारियों के पदों पर भर्ती की गई थी। भर्ती के लिए यह प्रक्रिया याचिकाकर्ताओं और अन्य योग्य उम्मीदवारों के स्पष्ट ज्ञान में थी, जिन्होंने स्वेच्छा से विभिन्न रोजगार कार्यालयों के साथ खुद को पंजीकृत किया और फिर साक्षात्कार में उपस्थित हुए। इस प्रकार यह कहा जाता है कि चयन समिति ने गुण-दोष के आधार पर उच्च स्तर के विचार के साथ निष्पक्ष रूप से कार्य किया है और किसी भी शर्त के सामने खुद को उजागर नहीं किया है और इसके द्वारा किया गया चयन कानूनी, न्यायसंगत, निष्पक्ष और पूरी तरह से संवैधानिक है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

10. निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रमाणित अपने लिखित बयान में यह जोड़ा गया है कि याचिकाकर्ता विधिवत गठित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे और चयन के लिए भी उन पर विचार किया गया था। ऐसा करने के बाद, याचिकाकर्ता चयन समिति के गठन या उसके द्वारा अपनाए गए चयन के तरीके के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते हैं और उन्हें अपने स्वयं के आचरण से रोक दिया जाता है। यह भी कहा गया है कि चयन करने के लिए एक मानदंड निर्धारित करना चयन समिति का कार्य था और समिति द्वारा निर्धारित मानदंड काफी उचित और नियमों और विनियमों के अनुसार हैं।

11. एक प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि केवल एक डिवीजनल अधिकारी नियम, 1955 के तहत नहर पटवारियों को नियुक्त करने के लिए सक्षम है और इस तरह की शक्तियों को किसी भी कार्यकारी निर्देशों द्वारा नहीं छीना जा सकता है। यह स्पष्ट किया गया है। अगस्त, 1979 में नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न सकलों में लगभग 250 नहरी पटवारियों की नियुक्ति की गई और किसी भी चयन बोर्ड द्वारा किसी भी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं की गई। वर्ष 1991 में फिर से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा किसी भी सिफारिश के बिना नियम, 1955 के अनुसार संभागीय अधिकारी द्वारा कैथल सर्कल में बीस नहर पटवारियों की नियुक्ति की गई।

12. हमने सर्वश्री आरके मलिक, राजीव आत्मा राम, आर.एस. सुरजेवाला, आई.एस. बलहारा, आईडी सिंगला और सुश्री वंदना अरोड़ा। इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील। हमने श्री एच एल स्वामीनाथन को भी सुना है। सिब्बल, एडवोकेट जनरल, हरियाणा, श्री कमल शर्मा द्वारा सहायता प्रदान की गई। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता सर्वश्री धर्मवीर शर्मा सूर्यकांत, डीडी शर्मा और के.के. उत्तरदाताओं की ओर से जगिया, अधिवक्ता।

13. याचिकाकर्ताओं के लिए केस खोलते हुए। याचिकाकर्ताओं के वकील श्री आरके मलिक ने तर्क दिया है कि एक बार नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है और नहर पटवारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाए हैं, तो सरकार के लिए इन नियमों को संशोधित या बदलने के लिए प्रशासनिक आदेश / परिपत्र / निर्देश जारी करना खुला नहीं है। यदि सरकार को लगता है कि नियम उन उद्देश्यों को पूरा नहीं करते हैं जिनके साथ वे तैयार किए गए हैं, तो सरकार के पास नियमों में संशोधन करने का एकमात्र रास्ता खुला है और नियमों में संशोधन केवल संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत शक्तियों का प्रयोग करके किया जा सकता है। संक्षेप में, श्री मलिक ने तर्क

दिया कि सरकार के पास कार्यकारी निर्देश जारी करके वैधानिक नियमों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार की प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों को दरकिनार करने या प्रतिस्थापित करने या संशोधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। श्री मलिक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि इन सांविधिक नियमों में कोई कमी है, तो उसे सरकार द्वारा कार्यकारी निर्देश जारी करके पूरा किया जा सकता है लेकिन नियम, 1955 में ऐसी कोई कमी नहीं थी। विद्वान वकील के अनुसार नियम, 1955 स्व-निहित हैं और नहर पटवारियों के पदों पर चयन और नियुक्तियों का एक विशिष्ट तरीका निर्धारित करते हैं और प्रतिवादी-सरकार के पास उन नहर/पटवारियों के चयन के लिए चयन समिति के गठन या अनुमोदन के लिए कोई शक्ति नहीं थी । यह भी तर्क दिया गया है कि एक बार चयन समिति का गठन कानून में खराब हो जाता है, तो उसके द्वारा किया गया चयन अवैध हो जाता है और नियमों से *परे* हो जाता है और रद्द किया जा सकता है। विद्वान वकील ने *हरियाणा* राज्य बनाम *शमशेर जंग बहादुर* [1], *श्री दुर्गाचरण मिश्रा* बनाम *उड़ीसा* राज्य [2], *पलुरु राम कृष्णैया* बनाम *भारत संघ* [3], *एके भटनागर* बनाम *हरियाणा राज्य मामले में दिए गए शीर्ष न्यायालय के कुछ फैसलों पर भरोसा जताया है। भारत संघ* [4] और *डॉक्टर कृष्ण चंद्र साहू* बनाम *उड़ीसा राज्य*[5]

14. विकल्प के रूप में यह तर्क दिया गया है कि तथाकथित चयन समिति का गठन अनुलग्नक आर.1 के तहत नहर पटवारियों के चयन के लिए स्वयं का कोई मानदंड निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं थी। ये मानदंड या तो सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों में संशोधन के माध्यम से या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकते थे जो नियमों के तहत संभागीय अधिकारी

[1] 1972 S.L.R. 441.
[2] 4 J.T. 1987 (3) S.C. 459.
[3] 1989 (2) Recent Services Judgments 153.
[4] (1991) 1 SCC 544.
[5] J.T. 1996 (7) S.C. 137.

है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंड अपने आप में अवैध और *अधिकार हीन* थे और उस पर आधारित कोई भी चयन रद्द किया जा सकता है। रिलायंस को *डॉक्टर कृष्ण चंद्र साहू के मामले* (सुप्रा) पर रखा गया है; *बी.एस. यादव* बनाम *हरियाणा राज्य* [6] और *आबकारी और कराधान आयुक्त, पंजाब* बनाम *जगन नाथ शर्मा* [7]

15. दूसरी ओर हरियाणा के महाधिवक्ता श्री हीरा लाल सिब्बल ने तर्क दिया है कि रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के प्रारंभ होने और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की स्थापना के बाद, नियम, 1955 का पालन नहीं किया गया था, और नहर पटवारियों के पदों पर चयन और नियुक्ति अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार साक्षात्कार के आधार पर की गई है।रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों का सम्मान। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि *निरंकुशता* के सिद्धांत के आधार पर, नियम, 1955 को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया गया था। उनकी दलील के समर्थन में पुणे *शहर नगर निगम* बनाम *भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड* मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा जताया गया है।[8]

16. आगे यह बताया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने जनता के साथ-साथ राज्य के हित में बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत विशेषज्ञों की एक चयन समिति का गठन किया, और इस चयन समिति ने साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन किया और शैक्षणिक योग्यता पर विचार करने के बाद तैयार वरिष्ठता सूची के अनुसार उनकी नियुक्तियों की सिफारिश की, नहर पटवार परीक्षा में योग्यता, अनुभव, अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ, खेल आदि। इस प्रकार यह तर्क दिया

[6] 1980 Supp SCC 524 : A.I.R. 1981 S.C. 561.
[7] 1980 (2) S.L.R. 744.
[8] J.T. 1995 (3) S.C. 312.

जाता है कि चयन समिति ने उम्मीदवारों की समग्र योग्यता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदंडों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश की, और इसे किसी भी तरह से मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है। इस विवाद के लिए भरोसा अंजार *अहमद* बनाम *बिहार राज्य* [9] मामले में शीर्ष अदालत के एक फैसले पर रखा गया है।

17. आगे यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता अपने दम पर चयन समिति द्वारा आयोजित मौखिक साक्षात्कार के रूप में उपस्थित हुए, जिसने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने उक्त मौखिक साक्षात्कार में खुद को चयनित करने का मौका लिया। एक बार जब वे सोच-समझकर मौका ले लेते हैं और साक्षात्कार में उपस्थित हो जाते हैं, तो केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उनके अनुकूल नहीं होता है, वे पलट नहीं सकते हैं और बाद में यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि चयन समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया था या साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित या नियम, 1955 के विपरीत थी। इसलिए, याचिकाकर्ता वर्तमान चयन या निजी उत्तरदाताओं की नियुक्तियों को सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दे सकते हैं। इस विवाद के लिए डॉक्टर *जी सरना* बनाम *लखनऊ विश्वविद्यालय (एससी)* [10], *स्वर्ण लता* बनाम *भारत संघ* [11], नॉर्थ मालाबार *ग्रामीण* बैंक *ऑफिसर्स एसोसिएशन* बनाम *नॉर्थ मालाबार* ग्रामीण *बैंक* [12] डॉक्टर के रूप *में रिपोर्ट किए* गए फैसलों पर भरोसा किया गया है*। (श्रीमती) एम थाहा* बनाम *राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान* [13], और *मदन लाल* बनाम *जम्मू और कश्मीर राज्य*[14]

---

[9] J.T. 1993 (6) 168.
[10] 1976 (2) S.L.R. 509.
[11] 1979 (1) S.L.R. 710 S.C.
[12] 1989 (3) S.L.R. 324 (Kerala).
[13] 1992 (4) S.L.R. 65 (A.P.).
[14] 1995 (2) Services Cases Today 880 (S.C.).

18. हरियाणा के एडवोकेट जनरल और निजी प्रतिवादियों के वकील की दलीलों को पूरा करते हुए। याचिकाकर्ताओं के वकील राजीव आत्मा राम ने तर्क दिया है कि एक बार नहरी पटवारियों के पदों को हरियाणा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के दायरे से बाहर कर दिया गया है, तो चयन नियम, 1955 के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए और साक्षात्कार के माध्यम से या अन्यथा कोई योग्यता या शर्त नहीं जोड़ी जा सकती है। विद्वान वकील द्वारा आगे बताया गया है कि चयन समिति ने 28 नवंबर, 1994 से 6 दिसंबर, 1994 के बीच उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था, जबकि कुछ पदों को हरियाणा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के दायरे से बाहर बताया गया है, दिनांक 25 जनवरी, 1995 (अनुबंध आर 3) और 2 मार्च, 2 मार्च के पत्र के माध्यम से, 1995 (अनुलग्नक आर 4)। यह भी बताया गया है कि नियमों के तहत एक डिवीजनल अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है, लेकिन वह तथाकथित चयन समिति में या उसके द्वारा किसी भी तरह से संबद्ध नहीं था । यह भी आग्रह किया गया है कि अनुलग्नक पी 2 एक सिफारिश नहीं है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां करने का निर्देश है। एक शक्ति का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें वह निहित है। इसका प्रयोग सरकार सहित कोई और नहीं कर सकता। इसलिए, अनुबंध पी 2 में निहित निर्देश के परिणामस्वरूप निजी प्रतिवादियों की नियुक्तियां कानून में खराब हैं क्योंकि चयन नियुक्ति प्राधिकारी का अंतिम निर्णय नहीं है, रिलायंस को विद्वान वकील द्वारा *आत्म प्रकाश मोहन* बनाम कुरुक्षेत्र *विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र* [15], *अमर सिंह* बनाम *पंजाब राज्य* [16] पर रखा गया है। और *प्रद्युत कुमार बोस* बनाम *कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश* [17]

19. प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई छूट/निष्कासन की याचिका को खारिज करने के लिए, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को कभी भी यह नहीं बताया गया था कि ऐसी कोई

---

[15] 1970 S.L.R. 16.
[16] 1983 (3) S.L.R. 264.
[17] A.I.R. 1956 S.T. 285.

चयन समिति गठित की गई थी और न ही उन्हें चयन के लिए उक्त समिति द्वारा अपनाए गए मानदंडों के बारे में किसी भी पत्र या अधिसूचना से परिचित कराया गया था। विद्वान वकील द्वारा यह समझाया गया है कि पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, याचिकाकर्ताओं और अन्य सफल उम्मीदवारों को संबंधित रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत किया गया था। रोजगार कार्यालय से पत्र प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता उक्त चयन समिति के गठन, इसकी शक्ति के स्रोत और चयन करने के लिए इसके द्वारा अपनाए गए मानदंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के बिना उक्त चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। निजी प्रतिवादियों की नियुक्ति के लिए कैथल सर्कल के डिवीजनल अधिकारी को नाम भेजे जाने के बाद ही याचिकाकर्ताओं को पता चला कि चयन समिति का गठन कैसे किया गया था और इसके द्वारा मानदंड निर्धारित किए गए थे जो नियमों के विपरीत था। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को चयन समिति के गठन और उसके द्वारा निर्धारित मानदंडों को चुनौती देने के अपने अधिकार को माफ नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में रिलायंस को *मोतीलाल पाडेम्पत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड* में दिए गए निर्णयों पर रखा गया है।बनाम *उत्तर प्रदेश* राज्य [18], *मानक लाल* बनाम *डॉक्टर प्रेम चंद सिंघवी* [19], *संसार चंद* बनाम *भारत संघ* [20] *और देविंदर सिंह* बनाम *हरियाणा राज्य*[21]

20. हमने बार में दिए गए संबंधित तर्कों पर विचार किया है। पक्षकारों की दलीलों और उनकी ओर से बार में उठाए गए विभिन्न तर्कों से, हम अपने उत्तर के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार करते हैं -

[18] (1979) 2 SCC 409 : A.I.R. 1979 S.C. 621.
[19] A.I.R. 1957 S.C. 425.
[20] 1980 (3) S.L.R. 124 (H.P.).
[21] 1988 (2) S.L.R. 412.

(1) क्या नियम, 1955 को निरंकुशता के सिद्धांत के आधार पर निरसित कर दिया गया *था*?

(2) क्या चयन समिति का गठन और चयन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदंड कानून में गलत हैं?

(3) क्या याचिकाकर्ताओं को चयन समिति के गठन की वैधता और चयन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदंडों को चुनौती देने से उनके आचरण से रोका जाता है?

(4) क्या चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें और निजी प्रतिवादियों की नियुक्तियां *असंवैधानिक* हैं?

प्रश्न संख्या 1:

21. यह विवादित नहीं है कि पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) पटवारी राज्य सेवा, तृतीय श्रेणी, नियम, 1955 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तैयार किया गया था। नियम 1 का उप-नियम (2) समय-समय पर संशोधित प्रशासन मैनुअल के पहले संस्करण के अध्याय 8 में मुद्रित पटवारी और मिराब से संबंधित नियमों का स्थान लेता है। नियम 2 में विभिन्न शब्दों की परिभाषा शामिल है। खंड (डी) 'अधीक्षण अभियंता' शब्द को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है एक नहर प्रणाली या सर्कल के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी। खंड (ई) 'डिवीजनल ऑफिसर' शब्द को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ एक डिवीजन के रूप में जाना जाने वाले क्षेत्र की नहर प्रणाली के एक हिस्से का प्रभारी अधिकारी है। खंड (जी) "सेवा" शब्द को पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा), पटवारी, राज्य सेवा वर्ग द्वितीय के रूप में परिभाषित करता है। नियम 3 में सेवा में शामिल किए जाने वाले पदों की संख्या शामिल है जैसा कि परिशिष्ट

'ए' में दिखाया गया है। नियम 4 और 5 में अपेक्षित राष्ट्रीयता और नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की आयु निर्धारित की गई है। नियम 6 नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है और निम्नानुसार पढ़ता है: -

"नियुक्ति के लिए योग्यता:

किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष की मैट्रिक या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, लेकिन उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी: -

बशर्ते कि अन्य चीजें समान हों, ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने खुद राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए काम किया है या कुछ उत्कृष्ट सामाजिक या सार्वजनिक सेवा प्रदान की है।

नियम 7 नियुक्ति के लिए अयोग्यता निर्धारित करता है। फिर नियम 8 में नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित किया गया। इसमें प्रावधान है -

"सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियां डिवीजनल अधिकारियों द्वारा की जाएंगी। नियम 9 एक आवेदन लोमड़ी नियुक्ति करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। नियम 10, 11 और 12 में भर्ती, प्रशिक्षण और पटवारी परीक्षा की विधि, एक सर्कल रजिस्टर के रखरखाव और नहर पटवारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये नियम निम्नानुसार हैं -

10. भर्ती की विधि:

(क) सेवाओं में नियुक्तियां सीधी नियुक्ति द्वारा की जाएंगी।

(ख) प्रभागीय अधिकारी प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए स्वीकृत उम्मीदवारों का एक रजिस्टर रखेगा। आगामी वर्ष के लिए रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक उम्मीदवारों की संख्या के दोगुने से अधिक उम्मीदवारों को स्वीकार किए गए उम्मीदवारों की सूची में नहीं लाया जाएगा और परीक्षा के लिए प्रशिक्षित और भेजा जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को संभागीय उम्मीदवार की सूची में नामांकन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इन नियमों के नियम 4, 5, 6, 7 और 9 में उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं करता है।

11. प्रशिक्षण और पटवार परीक्षा:

प्रत्येक स्वीकृत उम्मीदवार पटवारी को जिला अधिकारी अनुभाग में तैनात किया जाएगा जिसे नहर पटवारी के व्यावहारिक कर्तव्यों में कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उसे परिशिष्ट 'बी' में विस्तृत पटवार परीक्षा के भाग (iv), (v), (vi) और (vii) उत्तीर्ण करना होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर, जिलादार प्रत्येक स्वीकृत उम्मीदवार, जिसने इसे अर्जित किया हो, को भाग (iv) और (vi) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र देगा, जिसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी उम्मीदवार को दो बार से अधिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. उत्तीर्ण उम्मीदवारों का रजिस्टर:

(ए) सभी अभ्यर्थी, जो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, को परीक्षा उत्तीर्ण करने के क्रम में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के सर्कल रजिस्टर में लाया जाएगा। जब किसी डिवीजन में स्थायी रिक्ति होती है, तो अगले उत्तीर्ण उम्मीदवार को सर्कल रजिस्टर से तैनात किया जाएगा, भले ही वह सर्कल के किसी अन्य डिवीजन में छुट्टी या अस्थायी रिक्ति में सेवारत हो। नियुक्ति का आदेश संभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। पटवारी के रूप में

अस्थायी रूप से नियोजित किए बिना 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले उत्तीर्ण उम्मीदवार का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के मामले में इस अधिकतम आयु सीमा में सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित अवधि की सीमा तक, सरकार के अधीन सेवा में ऐसे उम्मीदवारों के प्रवेश के संबंध में छूट दी जाएगी और ऐसे उम्मीदवारों के नाम उस आयु तक सूची में बनाए रखे जाएंगे। अधीक्षण अभियंता का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष जनवरी की शुरुआत में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के सर्कल रजिस्टर की जांच करे, ताकि यह देखा जा सके कि अगले दो वर्षों के दौरान होने वाली सभी रिक्तियों को भरने के लिए रजिस्टर पर पर्याप्त उम्मीदवारों को वहन किया जाता है, और जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उम्मीदवार इस नियम के तहत निर्धारित अधिकतम आयु तक पहुंचने से पहले सामान्य रूप से स्थायी रोजगार प्राप्त करेंगे। सर्कल के सभी डिवीजनल अधिकारियों से युक्त एक चयन बोर्ड नियम 11 के अनुसार वर्ष के लिए प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए हर साल 1 जून से पहले बैठेगा।

(बी) किसी भी व्यक्ति को उत्तीर्ण उम्मीदवारों के सर्कल रजिस्टर में नहीं लाया जा सकता है जब तक कि उसने पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो।

फिर नियम 14 सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता निर्धारित करने की विधि निर्धारित करता है। यह निम्नानुसार है -

14. सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता: सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता का निर्धारण पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के क्रम क्रम में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के सर्कल रजिस्टर के अनुसार किया जाएगा। यदि परीक्षा में प्राप्त स्थिति समान है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के

मामले में, उनकी वरिष्ठता आयु से निर्धारित की जाएगी, एक छोटा सदस्य बड़े सदस्य से जूनियर है।

नियम 15 से 21 सेवा के सदस्यों के वेतन और बोनस का प्रावधान करते हैं; वह प्राधिकारी जो सेवा के सदस्यों को स्थानांतरित कर सकता है; अधिकारियों को दंड लगाने का अधिकार है; अवकाश, पेंशन और अन्य ठोस मामले आदि। परिशिष्ट 'ख' में पटवारी परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया, पाठ्यक्रम के साथ-साथ उक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भी प्रदान किया गया है।

22. उपर्युक्त नियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ये एक प्रकार से अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो पात्र होने के लिए योग्यता और शर्तें, चयन का तरीका और परीक्षा आयोजित करने और नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित करती है।

23. विद्वान महाधिवक्ता के तर्क को दोहराना। हरियाणा, यह तर्क दिया गया है कि नियम, 1955 के प्रारंभ होने के बाद, 1959 के अधिनियम संख्या XXXI के तहत गठित रोजगार कार्यालय के रूप में जाने जाने वाले दो वैधानिक निकाय और संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के मद्देनजर गठित पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आपस में जोड़ा गया था। इसके बाद, सभी उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया जा रहा था। उक्त अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा नहरी पटवारियों की भर्ती के लिए आवश्यक परीक्षा आयोजित की जा रही थी। इसके बाद उक्त बोर्ड द्वारा सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में समग्र प्रदर्शन के आधार पर, उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। इस प्रकार सर्कल स्तर पर एक रजिस्टर बनाए रखने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। एक उदाहरण के रूप में, उत्तर में यह उल्लेख किया गया है

कि वर्ष 1974 में नहरी पटवारियों की भर्ती के लिए परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित की गई थी, उम्मीदवारों को विभिन्न रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित किया गया था और उक्त बोर्ड द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया था और परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया गया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि नियम, 1955 सिद्धांत के आधार पर निहित रूप से निरस्त कर दिया गया *था*।

24. यह सही है कि हमारे देश में *अब निरंकुशता* के सिद्धांत को मान्यता और स्वीकार कर लिया गया है। *नगर निगम, पुणे के मामले* (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप में, इस बिंदु पर अंग्रेजी के साथ-साथ स्कॉटिश कानून को देखने के बाद, निम्नानुसार उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हुई: -

> "हालांकि भारत में अब तक यह कहने के लिए कि इस प्रक्रिया के कारण कोई क़ानून निरस्त हो गया है, हमें इस सिद्धांत को अपनी विधियों पर भी लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है। यही कारण है कि एक नागरिक को यह जानना चाहिए कि क्या एक क़ानून लंबे समय तक अप्रयुक्त होने के बावजूद और इसके बजाय एक विपरीत अभ्यास उपयोग में होने के बावजूद, उसे अभी भी 'मृत पत्र' के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि यह हमारे देश में भी निरंकुशता के सिद्धांत के अनुप्रयोग को स्वीकार करने के लिए न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा । हमारी मिट्टी इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार है; वास्तव में, इसके आरोपण की आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में रहने वाले व्यक्तियों, जिन्होंने अनुच्छेद 21 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को प्राप्त किया है, को एक ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने और दंडित किए जाने से बचाया जाना चाहिए जो 'मृत पत्र' बन गया है। इसलिए एक नया रास्ता तैयार करने और दबे कुचले जाने की जरूरत है।

उपर्युक्त निर्णय पर पहुंचने के लिए, उनके लॉर्डशिप ने *अन्य बातों के साथ-साथ* लॉर्ड मैके द्वारा *ब्राउन* बनाम *एडिनबर्ग मजिस्ट्रेट* [22]में व्यक्त किए गए विचारों पर भरोसा किया, जो निम्नानुसार हैं -

> "मैं कानून में यह स्पष्ट करता हूं कि कानून के संचालन के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है, न केवल उपेक्षा की, बल्कि इस तरह के चरित्र के विपरीत उपयोग के लिए व्यावहारिक रूप से समुदाय की ऐसी पूरी तरह से स्थापित आदत का अनुमान लगाने के लिए कि कानून का विरोध किया जाए या *अर्ध-निरसन* स्थापित किया जाए।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि *निरंकुशता* के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए, विचाराधीन क़ानून को लंबे समय तक अप्रयुक्त होना चाहिए और इसके बजाय एक विपरीत अभ्यास उपयोग में होना चाहिए। इस सिद्धांत के संचालन के लिए इस तरह के चरित्र के विपरीत उपयोग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि की आवश्यकता होती है क्योंकि समुदाय की इस तरह की पूरी तरह से स्थापित आदत का अनुमान लगाने के लिए व्यावहारिक है कि कानून का मुकाबला किया जा सके या अर्ध-निरसन स्थापित किया जा सके।

25. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-राज्य ने वर्ष 1974 का केवल एक उदाहरण दिया है जब नहर पटवारियों के पदों पर भर्ती परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की गई थी। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि अगस्त 1979 में, नियम, 1955 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न सर्किलों में लगभग 250 नहर पटवारियों को नियुक्त किया गया था और किसी भी चयन बोर्ड द्वारा किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की गई थी। यह भी बताया गया है कि वर्ष 1991 में अधीनस्थ सेवा चयन

---

[22] 1981 S.L.T. (Scots Law Times Reports) 456.

बोर्ड की किसी सिफारिश के बिना नियम, 1955 के अनुसार संभागीय अधिकारी द्वारा कैथल सर्कल में बीस नहरी पटवारियों की नियुक्ति की गई थी।

26 . इसके अलावा कार्यकारी अभियंता, फरीदाबाद मंडल/जीसी, फरीदाबाद (सिंचाई विभाग) द्वारा 1993 के सी.डब्ल्यू.पी. सं.6982 में श्री सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक से दायर लिखित वक्तव्य की एक प्रति को 1995 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 5516 के अभिलेख पर अनुलग्नक पी-2 के रूप में रखा गया है। यह लिखित बयान 28 जुलाई, 1993 को मुख्य अभियंता/नहरों (सिंचाई विभाग), हरियाणा, अधीक्षण अभियंता, डब्ल्यूजेसी फीडर/जीसी सर्कल, (सिंचाई विभाग) और कार्यकारी अभियंता, फरीदाबाद डिवीजन/जीसी, कैनाल कॉलोनी, फरीदाबाद की ओर से दायर किया गया था। इस लिखित विवरण के पैरा 2 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि हरियाणा राज्य में नहरी पटवारियों की नियुक्ति नियम, 1953 द्वारा शासित होती है और जिसके अनुसार प्रत्येक सर्कल में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का एक रजिस्टर मुख्य रूप से तैयार किया जाना है, और परीक्षा उत्तीर्ण करने के क्रमिक क्रम में पंजीकृत उम्मीदवारों में से विभागीय अधिकारियों द्वारा नियुक्ति की जानी है। उक्त लिखित विवरण के पैरा 4 में यह भी कहा गया है कि करनाल केंद्र में अप्रैल, 1992 के दौरान आयोजित पटवार परीक्षा का परिणाम 19 अप्रैल को घोषित किया गया था; 1993 में फरीदाबाद मंडल से संबंधित 59 उम्मीदवार और डब्ल्यूजेसी फीडर (जीसी सर्कल) के 94 अन्य उम्मीदवार; दिल्ली को सफल घोषित किया गया था, और इन उम्मीदवारों को उस सर्कल से पटवार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले पेटी-टियंस की तुलना में सर्कल के उम्मीदवार होने के नाते नियुक्ति का पूर्व कानूनी अधिकार था। प्रतिवादी-राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा की गई इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति से केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि नियम, 1955 अभी भी लागू हैं और संबंधित संभागीय

अधिकारियों द्वारा पटवार परीक्षा के आधार पर रखे गए रजिस्टर के अनुसार नियुक्तियां की जा रही हैं।

27. केवल यह तथ्य कि पिछले 30 वर्षों के दौरान, एक बार नहरी पटवारियों के पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से उसके द्वारा आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की गई थी, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि नियम, 1955 को निरंकुशता के सिद्धांत के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। *सी.सी. पद्मनाभन* बनाम *लोक शिक्षण निदेशक* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को निम्नानुसार समझाया:-

> "श्री अब्दुल खादर ने इस प्रस्ताव के खिलाफ जो एकमात्र तर्क दिया कि एईओ का पद उच्च श्रेणी में आता है, उसे इस प्रकार कहा जा सकता है। उपलब्ध नियमों और निर्देशों के अनुसार एक एचएसए, लेकिन एईओ नहीं, को हाई स्कूल के हेड-मास्टर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तथापि, सरकार एईओ की नियुक्ति करती रही है। हाई स्कूलों के हेडमास्टर के रूप में भी, जिसका अर्थ है कि ए.ई.ओ. H.S.As के बराबर हैं। अब यह कम से कम, एक अजीब तर्क है। यदि नियम ए.ई.ओ. की अनुमति नहीं देते हैं। हाई स्कूलों के हेडमास्टर बनने के लिए, लेकिन सरकार नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें इस तरह से तैनात कर रही है, यह पालन नहीं करेगी कि नियमों को उल्लंघन के अनुरूप पढ़ने के लिए स्वचालित रूप से संशोधित किया जाए।

अतः अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने नियमावली 1955 का उल्लंघन करते हुए भी वर्ष 1974 में केवल एक बार नहर पटवारियों के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा की होती तो उक्त नियमों की वैधानिकता एवं बाध्यकारी प्रभाव प्रभावित नहीं हो सकता था। यहां यह स्पष्ट किया जा सकता है कि राज्य ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने नहर पटवारियों की भर्ती के लिए वर्ष 1974 में क्या प्रक्रिया और

मानदंड अपनाए थे। अपनी दलीलों के अंत में, हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने काफी हद तक स्वीकार किया है कि लागू चयन में भी नियम 11 तक नियम, 1955 का पालन किया गया है, और यह केवल नियम 12 है जिसका पालन ऊपर बताए गए दो प्राधिकरणों की स्थिति के कारण नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार भी, नियम, 1955 का अभी भी पालन किया जा रहा है और गैर-उपयोगकर्ता द्वारा इसे निरस्त नहीं किया गया है।

28. यह जोड़ा जा सकता है कि राजेश कुमार नामक व्यक्ति ने 1995 की सिविल रिट याचिका संख्या 2867 दायर की थी, जिसमें हरियाणा राज्य, इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई विभाग, हरियाणा और मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, रोहतक को नहर पटवारियों के चयन को रद्द करने या याचिकाकर्ता को नहर पटवारी के रूप में चुनने और नियुक्त करने के लिए रिट जारी करने के लिए कहा गया था क्योंकि उस मामले में प्रतिवादी नंबर 4 जैसे योग्यता में नीचे के व्यक्ति थे। चयनित किया गया, जबकि याचिकाकर्ता के सही दावे को मनमाने ढंग से नजरअंदाज कर दिया गया था। इस रिट याचिका का राज्य या अन्य आधिकारिक प्रतिवादियों द्वारा कभी विरोध नहीं किया गया। उक्त रिट याचिका को स्वीकार करते हुए और याचिकाकर्ता को नहर पटवारी के रूप में चुनने और नियुक्त करने के निर्देश जारी करते हुए, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 17 जुलाई, 1995 के आदेश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: -

> पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 10+2 की परीक्षा और नहरी पटवार परीक्षा पास की है। 10+2 परीक्षा में उन्होंने 400 में से 156 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने नहर पटवार परीक्षा उत्तीर्ण की है और 375 अंकों में से 292 अंक प्राप्त किए हैं। रिट याचिका के पैराग्राफ 3 में, याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4, ने नहर पटवार परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी उसे

याचिकाकर्ता के दावे की अनदेखी करते हुए उसके लिए प्राथमिकता दी गई है और नियुक्ति दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि चौथा उत्तरदाता केवल मैट्रिक पास है। पैराग्राफ नंबर 4 और 5 में, चौथे प्रतिवादी को नियुक्ति देने में उत्तरदाताओं के खिलाफ दुर्भावना से अपील की गई है। जहां तक *दुर्भावना* का संबंध है, हम इस स्तर पर एक या दूसरे तरीके से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, जिसने नहर पटवार परीक्षा में प्रतिवादी संख्या 4 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, को नहर पटवारी के रूप में नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने चौथे प्रतिवादी को नियुक्ति देते समय याचिकाकर्ता की योग्यता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

यह रिट अपने निर्णय और उसमें की गई टिप्पणियों के साथ इस निष्कर्ष को और मजबूत करती है कि नियम, 1955 अभी भी लागू हैं और बिना किसी परिवर्तन या संशोधन के हरियाणा राज्य में नहर पटवारियों की नियुक्ति में उनका पालन किया जा रहा है।

29. तदनुसार, हमें इस बिंदु पर विद्वान महाधिवक्ता के तर्क में कोई दम नहीं दिखता। तदनुसार इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है।

प्रश्न संख्या 2:-

30. यह माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य सभी स्वीकृत उम्मीदवारों ने, जैसा कि नियम, 1955 के नियम 11 द्वारा परिकल्पित किया गया है, अपने संबंधित जिलेदारों के साथ अपने पटवार त्रिशंकु को पारित किया। उक्त प्रशिक्षण को पूरा करने और नियमों के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, वे 25 अप्रैल, 1992 से 28 अप्रैल, 1992 तक हरियाणा राज्य के चार अलग-अलग क्षेत्रों में आयोजित पटवार परीक्षा में उपस्थित हुए। परिणाम वर्ष 1993 में कहीं घोषित किया गया था। सफल उम्मीदवारों को अपने संबंधित जिला रोजगार कार्यालयों में खुद को पंजीकृत करने के लिए कहा गया था। 6 अक्तूबर, 1994 को हरियाणा

सरकार के वित्तीय आयुक्त और सचिव, सिंचाई एवं विद्युत विभाग ने एक ज्ञापन भेजा। (अनुलग्नक आर 1) दिनांक 6 अक्तूबर, 1994 को इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ को भेजा गया है, जो निम्नानुसार है -

विषय - सिंचाई विभाग, हरियाणा में नहरी पटवारियों और अपरेंटिस नहर पटवारियों की रिक्तियों को भरना। ऊपर उल्लिखित विषय पर दिनांक 11 अगस्त, 1594 के अपने यू.ओ. सं. 5817/6एनजीई-II का संदर्भ लें।

2. उन नहरी पटवारियों के चयन के लिए चयन समिति के गठन के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिनके पदों को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है।

अध्यक्ष	... सीई वाईडब्ल्यूएस यूनिट
सदस्य	... सीई बीडब्ल्यूएस यूनिट
सदस्य-सचिव	... जीएम (पी) सिंचाई विभाग।
सदस्य	... डिप्टी कलेक्टर, बीडब्ल्यूएस/सी कैथल
सह-चयनित सदस्य	... एक्सईएन नहर, हिसार।

3. आपसे अनुरोध है कि इस मामले में तुरंत आगे बढ़ें।

एसडी/-

अवर सचिव/सिंचाई एवं विद्युत

वित्तीय आयुक्त और सचिव के लिए

सरकार, हरियाणा, सिंचाई और बिजली विभाग।

तदनुसार, विभिन्न रोजगार कार्यालयों ने इन अभ्यथयों को साक्षात्कार दिए जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अपने कार्यालयों में बुलाया और अंतत उन्हें उक्त समिति को भेज दिया गया। समिति द्वारा 28 नवम्बर, 1994 से 6 दिसम्बर, 1994 तक इन अभ्यथयों का साक्षात्कार लिया गया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने चयन करने के लिए उक्त समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों की एक प्रति प्रदान की जो मार्क 'सीआई' है। इसमें निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं -

"मार्क 'सी.1'

शैक्षिक योग्यता

मैट्रिक तीसरा संस्करण।	= 20	
मैट्रिक 2, तैयारी या +1	= 21	
मैट्रिक 1 + एसएसएलसी + 2	= 22	
+2 1 4-बीए भाग I और II	= 23	
बी.ए.	= 24	
बीए प्रथम या एमए या		
बी.एड. आदि।	= 25	25

पटवार परीक्षा

230-240	=	20	
241-260	=	21	
261-280	=	22	
281-290	=	23	
291-300	=	24	
301 +	=	25	25
खेल-कूद	=	5	
अनुभव	=	10	
पाठ्यक्रमेतर	=	5	20
मौखिक परीक्षा	=	30	30
कुल अंक	=	100	100

समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर, चयनित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की गई थी और चयनित उम्मीदवारों को संबंधित अधीक्षण अभियंताओं द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार सर्कल-वार आवंटित किया गया था। दिनांक 3 फरवरी, 1995 के पत्र की एक प्रति (अनुलग्नक पी 2) सी.डब्ल्यू.पी. सं. 4283 में दायर की गई है। 1995 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है -

विषय: - सिंचाई विभाग, हरियाणा में नहर पटवारी की नियुक्ति।

ऊपर उल्लिखित विषय पर दिनांक 2 फरवरी, 1993 के मेरे यूयू नोट संख्या 135-39, ओआई (पी) को जारी रखते हुए।

समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सभी श्रेणियों को कवर करते हुए एक संयुक्त मेरिट तैयार की गई है और उम्मीदवारों को आपकी लाइन इकाइयों के एसई द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार उनकी योग्यता देते हुए सर्कलवार आवंटित किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि सेवा नियमों के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से इन उम्मीदवारों को संबंधित रोजगार कार्यालयों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं।

आपकी यूनिट को आवंटित उम्मीदवारों की सूची, प्रत्येक के खिलाफ इंगित योग्यता के अनुसार सर्कलवार आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

उदाहरण के लिए:–जैसा कि ऊपर बताया गया है।

सीसी: जानकारी के लिए आरसीआईपी।

इस सामग्री को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना है कि क्या चयन समिति का गठन - पत्र अनुलग्नक आर 1 के माध्यम *से*, चयन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड - अनुबंध 'सी 1' *के माध्यम* से और इसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों का चयन कानून में वैध है?

31. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक बार नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लिया है और विशेष पद के लिए व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम तैयार किए हैं, तो सरकार के लिए इन नियमों को संशोधित या परिवर्तित करने के लिए कोई

प्रशासनिक आदेश / परिपत्र / निर्देश जारी करना खुला नहीं है। यदि सरकार को लगता है कि नियम उन उद्देश्यों को पूरा नहीं करते हैं जिनके साथ वे तैयार किए गए हैं, तो उसके पास एकमात्र रास्ता खुला है कि वह संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नियमों में संशोधन करे। यदि नियमों में कोई कमी है, तो उसे निश्चित रूप से कार्यकारी अनुदेशों द्वारा भरा जा सकता है लेकिन सरकार के पास अनुदेशों/परिपत्रों द्वारा किसी विशेष पद के लिए किसी उम्मीदवार की पात्रता या उपयुक्तता के संबंध में कोई अतिरिक्त आवश्यकता निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं है।

32. *ए.के. भटनागर के मामले* (सुप्रा) में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा चेतावनी दी गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बनाए गए नियम प्रकृति में गंभीर हैं जो बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। *श्री दुर्गाचरण मिश्रा के मामले* (सुप्रा) में शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और चयन उनके अनुसार किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि चयन समिति द्वारा पात्रता या उपयुक्तता के रूप में चयन के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकता निर्धारित नहीं की जा सकती है। *शमशेर जंग बहादुर के मामले* (सुप्रा) में भी शीर्ष अदालत ने इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं।

33. ऊपर पहले ही कहा जा चुका है कि नहरी पटवारियों की भर्ती के लिए उनकी सेवा शर्तें सांविधिक नियम, 1955 अधिनियमित किए गए हैं। ये नियम अपने आप में नहर के चयन और नियुक्ति के लिए एक पूर्ण योजना प्रदान करते हैं। पटवारी। भर्ती की विधि और नियुक्ति का तरीका नियम 10 से 12 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। नियम 8 के अनुसार, सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियां मंडल अधिकारियों द्वारा की जाएंगी। नियमों के परिशिष्ट ख में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वृत्त के लिए पटवार परीक्षा मंडल अधिकारी

द्वारा बारी-बारी से आयोजित की जाएगी। एक संभागीय अधिकारी को उक्त परिशिष्ट में वर्णित विषयों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की जांच करने के उद्देश्य से एक बोर्ड बुलाने का अधिकार है, जिसमें अध्यक्ष और डिप्टी कलेक्टर और एक उप-विभागीय अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस प्रकार, किसी भी नियम में किसी अन्य चयन समिति के गठन या पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

34. इसलिए, चयन समिति का गठन या प्रतिवादी-राज्य द्वारा उसके संविधान को दिया गया अनुमोदन- अनुबंध आर 1 के *माध्यम से* नियम, 1955 का सीधा उल्लंघन है। उपर्युक्त चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर साक्षात्कार की आवश्यकता, जिसे ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, उपयुक्तता के रूप में चयन के लिए एक अतिरिक्त आवश्यकता है जिसकी वैधानिक नियमों द्वारा अनुमति नहीं है और इसे अवैध और बिना अधिकार के कहा जाएगा।

35. यह रेखांकित करने योग्य है कि कार्यकारी अनुदेशों वाले अनुलग्नक आर.1 को प्रतिवादी-राज्य द्वारा स्वयं जारी किया गया था, न कि किसी संभागीय अधिकारी द्वारा, जिसमें नहर पटवारियों की नियुक्ति की शक्ति नियम, 1955 द्वारा निहित है। यदि स्थिति ऐसी होती, तो शायद यह तर्कहीन हो सकता है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने या तो अपनी शक्तियों को सौंप दिया था या अपनी सहायता के लिए केवल एक सलाहकार निकाय बनाया था। हालांकि, यह यहां दूर-दूर तक मामला नहीं है। चयन समिति का गठन संभागीय अधिकारी के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया था। इसने मंडल अधिकारी में नियमों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की शक्तियों को वस्तुतः दरकिनार कर दिया। इस आलोक में, हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि कार्यकारी अनुदेशों (अनुलग्नक आर. 1) और चयन समिति के गठन को या तो

नियमों के प्रति याचक या उनमें एक अंतर को भरने के रूप में नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अनुलग्नक आर 1 के अनुसार चयन समिति का गठन अपने आप में अवैध है। *जगन नाथ शर्मा* के मामले (सुप्रा), *श्री रविंदर कुमार* बनाम पंजाब *राज्य* (22) और *पलविंदर सिंह* बनाम *लोक शिक्षण निदेशक पंजाब* [23] के मामले में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं।

36. यह मामला कृष्ण *चंद्र साहू के मामले* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है । उस स्थिति में जूनियर शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की जानी थी। चयन प्रक्रिया उड़ीसा होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षण सेवा (भर्ती के तरीके और सेवा की शर्तें) नियम, 1980 द्वारा शासित थी। संबंधित नियम उन दिशानिर्देशों के बारे में चुप था जिनके आधार पर उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन किया जाना था। सरकार ने इस संबंध में कोई प्रशासनिक अनुदेश जारी नहीं किए थे। चयन बोर्ड ने उक्त मानदंड के आधार पर उक्त समिति द्वारा उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए स्वयं उसके द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंड निर्धारित किए थे और उनकी नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। यह मानते हुए कि चयन बोर्ड द्वारा अपनाया गया आधार प्राधिकार या अधिकार क्षेत्र के बिना होने के अलावा पूरी तरह से मनमाना था, उनके लॉर्डशिप ने कानून को निम्नानुसार बताया: -

> "अब, सरकारी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत राज्य के राज्यपाल के पास उपलब्ध है और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियम बनाए गए थे। यदि किसी दिए गए मामले में सांविधिक नियम संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा या उस मामले के

[23] 1983 (1) S.L.R. 271.

लिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं बनाए गए हैं, तो कार्यकारी निर्देश जारी करना उपयुक्त सरकार (अनुच्छेद 73 के तहत केंद्र सरकार और अनुच्छेद 162 के तहत राज्य सरकार) के लिए खुला होगा। हालांकि, यदि नियम बनाए गए हैं, लेकिन वे किसी भी विषय या मुद्दे पर चुप हैं, तो चूक की आपूर्ति की जा सकती है और नियमों को कार्यकारी निर्देशों द्वारा पूरक किया जा सकता है (देखें: *संत राम* बनाम *राजस्थान राज्य* (1967 एससी 1910)।

इस मामले में, सरकार ने न तो कोई प्रशासनिक निर्देश जारी किया और न ही उन मानदंडों के संबंध में चूक की आपूर्ति की जिनके आधार पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित की जानी थी। चयन बोर्ड के सदस्यों ने अपनी उपयुक्तता निर्धारित करने के आधार के रूप में उन उम्मीदवारों के गोपनीय चरित्र नामावली को अपनाने का निर्णय लिया जो पहले से ही होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के रूप में कार्यरत थे।

चयन बोर्ड या उस मामले के लिए, किसी अन्य चयन समिति के सदस्यों को चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वे अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विशेष रूप से उस संबंध में अधिकृत न हों। यह मूल रूप से चयन के लिए आधार प्रदान करने के लिए नियम बनाने वाले प्राधिकरण का कार्य है। *आंध्र प्रदेश राज्य* बनाम *सदानंदम* (जे.टी. 1989 (सुप.) एस.सी. 232: 1989 सुप्प (1) एससीसी 574 : ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 2060) मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> पीठ ने कहा, "हमारे पास अब न्यायाधिकरण का केवल यह तर्क बचा है कि पुराने नियमों को जारी रखने और दोनों क्षेत्रों से संबंधित कर्मियों को अन्य क्षेत्रों के कार्यालयों में पदोन्नति पर स्थानांतरित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तरह का निष्कर्ष निकालने में, ट्रिब्यूनल ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे यात्रा की है। हमें

केवल यह बताने की आवश्यकता है कि भर्ती का तरीका और जिस श्रेणी से किसी सेवा में भर्ती की जानी चाहिए, ये सभी मामले हैं जो विशेष रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह न्यायिक निकायों का काम नहीं है कि वे भर्ती के तरीके या उन श्रेणियों को चुनने में कार्यपालिका के विवेक पर निर्णय लें जिनमें से भर्ती की जानी चाहिए क्योंकि वे नीतिगत निर्णय के मामले हैं जो विशेष रूप से कार्यपालिका के दायरे में आते हैं।

उनके लॉर्डशिप को यह देखते हुए प्रसन्नता हुई कि चयन समिति के पास चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र भी नहीं है और न ही ऐसी शक्तियों को आवश्यक निहितार्थ द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। फिर निर्णय के पैरा 38 में, उनके लॉर्डशिप ने कानून को निम्नानुसार समझाया: -

"यह इंगित किया जा सकता है कि अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने का कार्य विधायी है, न कि कार्यकारी, जैसा कि इस न्यायालय ने *बीएस यादव* बनाम *हरियाणा राज्य*, (1980 एसयूपीपी एससीसी 524: एआईआर 1981 एससी 561) में निर्धारित किया था। इस कारण से भी, चयन समिति या चयन बोर्ड को चयन के लिए कोई मानक या आधार निर्धारित करने का अधिकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह चयन के नियम को वैध बनाने के समान होगा।

वर्तमान मामला उपरोक्त मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

37. यह मानते हुए भी कि चयन समिति का गठन एक प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए कार्यकारी निर्देशों द्वारा किया गया था, इसके पास नहर पटवारियों के लिए चयन करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं था। उक्त चयन समिति के पास

चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए भी कोई अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र नहीं था। फिर भी, चयन समिति को चयन के लिए कोई मानक या आधार निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह चयन के नियम को कानून बनाने के बराबर होगा। हम यहां यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अनुबंध आर 1 में निहित कार्यकारी अनुदेशों से पता चलता है कि इस प्रकार गठित चयन समिति केवल एक सलाहकार या तथ्यान्वेषी निकाय नहीं थी, बल्कि वास्तव में नहर पटवारियों की नियुक्तियों की शक्ति के साथ निहित थी, जो अन्यथा नियमों द्वारा विभागीय अधिकारी के हाथों में थी। वर्तमान मामले में अनुलग्नक आर.1 और 1995 के सी.डब्ल्यू.पी.एन. अम्बर 4283 के अनुलग्नक पी.2 को संयुक्त रूप से पढ़ने से हमें लगता है कि नियम 8 के पूरक होने के बजाय, यह वस्तुतः डिवीजनल अधिकारी से चयन समिति में नियुक्ति की शक्ति को प्रतिस्थापित करने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे यह नियम मात्र रबर स्टैंप के रूप में प्रस्तुत होता है। इन कार्यकारी अनुदेशों का आशय और उद्देश्य नियम, 1955 के नियम 8 के बिल्कुल विपरीत है और इसके साथ स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है।

38. एक अन्य तथ्य जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि चयन समिति ने चयन के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं जैसा कि अनुबंध 'सी 1' में निहित है। इसने उक्त मानदंडों को 6 उप-प्रमुखों में विभाजित किया और उनमें से प्रत्येक के लिए अंक आवंटित किए। बहस के दौरान, हमारे निर्देश पर प्रतिवादी-राज्य ने उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद चयन समिति द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड को प्रस्तुत किया। हमारे विशिष्ट निर्देश के बावजूद कोई अन्य रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया है। प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि चयन समिति ने प्रत्येक उम्मीदवार को एकमुश्त अंक दिए हैं। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पेश किया गया है कि उम्मीदवारों को मदवार आधार पर अंक दिए गए थे। यह स्पष्ट रूप से अवैध है और इस सरल कारण के लिए साक्षात्कार दूषित है। इस दृष्टिकोण की

पुष्टि माइनर *ए सेरियाकारुगन* बनाम *तमिलनाडु राज्य* [24]मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में होती है।

39. इस मामले में एक और दिलचस्प कोण है। नहरी पटवारियों की भर्ती के लिए परीक्षा 25 अप्रैल, 1992 से 28 अप्रैल, 1992 तक हुई थी। परिणाम 1993 में घोषित किया गया था। चयन समिति का गठन दिनांक 6 अक्तूबर, 1994 के ज्ञापन (अनुपत्र आर 1) के तहत किया गया था। बेशक, चयन समिति ने 28 नवंबर, 1994 से 6 दिसंबर, 1994 तक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया। नहरी पटवारियों के पदों को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया था- दिनांक 4 अक्टूबर, 1995 (अनुलग्नक आर 2), 25 जनवरी, 1995 (अनुलग्नक आर 3) और 2 मार्च, 1995 के ज्ञापन (अनुलग्नक आर 4)। इस प्रकार तथाकथित साक्षात्कार पूरा होने के काफी बाद नहरी पटवारियों के अधिकांश पदों को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के दायरे से बाहर कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, चयन समिति ने अंडे से निकलने से पहले अपनी मुर्गियों की गिनती शुरू कर दी थी।

40. इसलिए, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि चयन समिति का गठन अपने आप में अवैध और वैधानिक नियमों के विपरीत था। हम आगे मानते हैं कि इस चयन समिति के पास उक्त चयन के लिए कोई मानदंड निर्धारित करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं था। हम आगे मानते हैं कि समिति द्वारा किया गया चयन न केवल नियमों के विपरीत है, बल्कि चयन के मानदंडों का उल्लंघन है। तदनुसार इस प्रश्न का उत्तर हां में दिया गया है।

प्रश्न संख्या 3:

[24] (1971) 1 SCC 38

41. उत्तरदाताओं की ओर से, छूट की दलील पर मजबूत भरोसा रखा गया है। उनके अनुसार, एक बार जब याचिकाकर्ता स्वेच्छा से चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए और खुद को चयनित करने का मौका लिया, तो केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उनके अनुकूल नहीं है, वे पलट नहीं सकते हैं और बाद में तर्क दे सकते हैं कि चयन समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया था या साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित या नियमों के विपरीत थी। 1955. यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त याचिका तब भी प्रभावित नहीं होती है जहां ट्रिब्यूनल में अधिकार क्षेत्र की कुल कमी होती है। रिलायंस को कतिपय निर्णयों पर रखा गया है जिन पर बाद में ध्यान दिया जाएगा।

42. हमारे अनुसार, यह कहना कठिन है कि तथ्यों के आधार पर, छूट की दलील को राज्य-सरकार द्वारा या उत्तरदाताओं द्वारा उस मामले के लिए कैसे कहा जा सकता है। *मोतीलाल पदमगत चीनी मिल्स* मामले में उत्तर *प्रदेश राज्य के* विरुद्ध राज्य सरकार का *अनुकरण किया गया* छूट शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है -

> "छूट का अर्थ है एक अधिकार का परित्याग और यह या तो व्यक्त हो सकता है या आचरण से निहित हो सकता है, लेकिन इसकी मूल आवश्यकता यह है कि यह ज्ञान के साथ एक जानबूझकर कार्य होना चाहिए। कोई छूट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने माफी की है, उसे उसके अधिकार के बारे में पूरी तरह से सूचित नहीं किया जाता है और इस तरह के अधिकार की पूरी जानकारी के साथ वह जानबूझकर इसे छोड़ देता है।

इस प्रकार, कोई छूट नहीं हो सकती है जब तक कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने माफी की है, उसे उसके अधिकार के बारे में पूरी तरह से सूचित नहीं किया जाता है और इस तरह के अधिकार की पूरी जानकारी के साथ, वह जानबूझकर इसे माफ कर देता है। इसी

तरह के विचार शीर्ष अदालत ने *मानक लाल* बनाम *डीऑक्टर प्रेम चंद सिंघवी* [25] के मामले में व्यक्त किए हैं।

43. *डीऑक्टर जी सरना के मामले* (सुप्रा) में प्रतिवादियों द्वारा भरोसा किया गया, अपीलकर्ता चयन समिति के समक्ष जानबूझकर बहुत अच्छी तरह से पेश हुआ कि उनकी संख्या कौन थी। उन्होंने चयन समिति के गठन के खिलाफ कभी कोई आपत्ति नहीं जताई और नियुक्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 8 की सिफारिश करने का संकल्प लिया। उक्त सिफारिश के बारे में पता चलने पर, अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करके सिफारिश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी कि चयन समिति का गठन करने वाले तीन विशेषज्ञों में से दो उसके खिलाफ और प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में पक्षपातपूर्ण थे। इन तथ्यों पर शीर्ष अदालत ने कहा:

> "वर्तमान मामले में पूर्वाग्रह की तर्कसंगतता या पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना के सवाल पर जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता सभी प्रासंगिक तथ्यों को जानता है, उसने साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पहले या साक्षात्कार के समय चयन समिति के गठन के खिलाफ अपनी छोटी उंगली भी नहीं उठाई। ऐसा लगता है कि वह स्वेच्छा से समिति के समक्ष पेश हुए हैं और समिति से अनुकूल सिफारिश करने का मौका लिया है। ऐसा करने के बाद, अब उनके पास पलटना और समिति के गठन पर सवाल उठाना नहीं है।

इसी तरह *स्वर्ण लता के मामले* (सुप्रा) में यह पाया गया कि अपीलकर्ता उसे दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा था। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के जवाब में उन्होंने स्वेच्छा से, और बिना किसी के अनुनय के, स्वेच्छा से और बिना किसी के अनुनय

---

[25] A.I.R. 1957 S.C. 423.

के, पद के लिए आवेदन किया था। इसलिए, उन्होंने अपना मौका लिया और केवल इसलिए कि चयन समिति ने उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया, यह देखा गया कि उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 का चयन अमान्य था, क्योंकि केंद्र सरकार या आयोग द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत होने के कारण इसकी शक्तियों का उल्लंघन किया गया था। इसी तरह के तथ्यों पर इसी तरह का विचार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने *डीअक्टूबर (श्रीमती) एम थाहा के मामले* (सुप्रा) में व्यक्त किया था। *नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के मामले* (सुप्रा) में, दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधकों के चयन के लिए, पहले प्रतिवादी ने एक परिपत्र जारी किया, जिसमें उन मानदंडों को निर्धारित किया गया था जो चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को अंक देने का प्रावधान करते थे। पहले प्रतिवादी ने एक परिपत्र भी जारी किया जिसमें अधिकारियों को क्षेत्र प्रबंधकों/वरिष्ठ प्रबंधकों के चार पदों पर चयन के बारे में सूचित किया गया। इस प्रकार, क्षेत्र प्रबंधकों / वरिष्ठ प्रबंधकों के चयन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद, याचिकाकर्ता साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए लेकिन सफलता नहीं मिली। इन तथ्यों पर, यह माना गया कि पूरी तरह से जानने के बाद कि इस तरह की चयन प्रक्रिया से गुजरना है और साक्षात्कार में भाग लेने और पदोन्नति पाने का मौका लेने के बाद, याचिकाकर्ताओं को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि पदोन्नति के लिए अपनाई गई विधि अवैध थी। *जिला थोक सहकारी* बनाम *उप रजिस्ट्रार* [26] में पहले के फैसले का संदर्भ दिया गया था, जो ट्रिब्यूनल में अधिकार क्षेत्र की कुल कमी के मामले से निपटता था। उस मामले में भी यह माना गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के विवेकाधिकार का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता है जिसने इस बिंदु पर कोई आपत्ति उठाए बिना उससे अनुकूल निर्णय प्राप्त करने का

---

[26] A.I.R. 1975 K.L.T. 589.

मौका लिया। *मदन लाल के मामले* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी संदर्भ दिया गया है , जिसमें इसी तरह का कानून निर्धारित किया गया है।

44. उपरोक्त उद्धृत उदाहरणों में से कोई भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। प्रतिवादियों द्वारा यह नहीं बताया जा सका कि याचिकाकर्ताओं को पहले से कोई संचार भेजा गया था जिसमें यह संकेत दिया गया था कि पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें किसी भी चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा, न ही उन्हें उनके पदनामों के साथ उन व्यक्तियों के बारे में सूचित किया गया था जिन्होंने साक्षात्कार के लिए चयन समिति का गठन किया था। याचिकाकर्ताओं को चयन समिति द्वारा निर्धारित तथाकथित मानदंडों के बारे में भी कभी नहीं बताया गया, जिसके आधार पर नहर पटवारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाना था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले याचिकाकर्ताओं ने समिति के गठन या चयन के लिए निर्धारित मानदंडों को चुनौती देने के अपने अधिकार को छोड़ दिया । याचिकाकर्ताओं की ओर से इस दावे का विरोध करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि उन्हें चयन समिति के गठन या इसके द्वारा निर्धारित मानदंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और उन्हें पहली बार इसके बारे में पता चला जब चयनित उम्मीदवारों की एक सूची भाखड़ा जल सेवा सर्कल के कार्यालय में प्राप्त हुई। नियुक्ति के लिए कैथल। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने चयन समिति के गठन और चयन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंडों को चुनौती देने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, जो नियम, 1955 के विपरीत है। इसलिए, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है।

45. प्रश्न संख्या 1 से 3 के अपने उत्तर में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 28 नवंबर, 1994 से 6 दिसंबर, 1994 तक आयोजित साक्षात्कार के परिणामस्वरूप चयन समिति द्वारा की गई चयन और सिफारिशें और इसके परिणामस्वरूप निजी प्रतिवादियों, या उस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्तियां अवैध हैं और नियमों के *विपरीत* हैं , 1955.

46. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। नहर पटवारियों के रूप में निजी प्रतिवादियों के चयन और नियुक्ति को रद्द किया जाता है। आधिकारिक प्रतिवादियों को सिंचाई विभाग, हरियाणा में नहर पटवारियों के पदों पर नियम, 1955 के अनुसार सख्ती से नियुक्तियां करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उक्त पदों पर नियुक्ति करते समय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जिन्हें 25 अप्रैल, 1992 से 28 अप्रैल, 1992 तक आयोजित नहरी पटवारी परीक्षा में सफल घोषित किया गया हो और उक्त नियमों के तहत अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी नियुक्तियां करते समय आधिकारिक उत्तरदाता संवैधानिक या विधायी आरक्षणों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखेंगे। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा